[श्रीमति टी॰ लक्ष्मीकान्तम्मा]

लाने मे ससद् को कोई कठिनाई नही होनी चाहिए। इसका उल्लेख राष्ट्रपति जी के भाषण मे भी होता तो ज्यादा अच्छा होता। इस दिशा मे भारत सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यक्रम का वर्णन अगर भाषण मे होता तो अच्छा होता। एक लेख मे श्री आर॰ डी॰ मलिक ने कहा है कि इस देश मे महिलाओ की क्रान्ति इतनी ढीली क्यो है ? इसके बारे मे वे कहते है कि महिलाओं के उद्धार मे विलम्ब होने की जिम्मवारी हम पर है, जो महिला ससद् सदस्य या मिनिस्टर है, इन सब पर ह । ससद् सदस्यो ने महिलाओं के उत्थान को अपने विशेष उत्तरदायित्व के रूप मे स्वीकार किया ही नही। हम इस बात को स्वीकार करते है कि इतने वर्षों मे हम ससद् सदस्यो ने जो किया है उस पर अगर विचार करे तो पायेगे कि बहुत कम काम किया है। और बहुत कर सकते थे, जो कि हम ने नही किया है।

सभापति महोदय, कम से कम सोशलिस्ट कन्ट्रीज मे कुछ प्रयास हुआ है । मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त से बाहर पूछा कि महिलाओ के बारे मे कुछ थोडा सा बोलिये। हमारे देश मे कोई भी पार्टी हो मेरे ख्याल मे बूर्जुआ की तरह है । महिलाओ की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के लिये सरकार ने एक समिति बनायी थी और उस ने हाल ही मे अपनी रिपोर्ट दी है जिस के अनुसार महिलाओ की दशा कई क्षेत्रो मे अत्यन्त दयनीय है। यह बात भी स्पष्ट होती है हमारे सविधान और अन्य कानूनो द्वारा दिये गये समान अधिकारो से भारत की ग्रामीण महिलाये बडी हद तक वचित रही ह और उन के जीवन मे कोई परिवर्तन नही आया है । यह रिपोर्ट मे लिखा गया है। नारी जाति का राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक उद्धार बडी हद तक नगर समाज तक ही सीमित रहा है। देश के देहातो मे फैली हुई कोटि-कोटि महिलाओ को उसका फल नही मिला और कोई सभावना भी निकट भविष्य में नही दिखती ।

MR CHAIRMAN Now it is 5-30 p m We have to pass on to the next item The hon. Member may continue her speech tomorrow

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा . सभापति जी, मैं अनुरोध करती हू कि हमको ज्यादा टाइम दिया जाय ।

MR CHAIRMAN We shall see tomorrow

---

17 30 hrs.

HALF AN-HOUR DISCUSSION

Issue of import licences for Polyester Fibre

MR CHAIRMAN We now take up the half an hour discussion Shri Madhu Limaye to raise it

श्री मधु लिमये (बाका) सभापति महोदय, 6 दिसम्बर को जो तारांकित प्रश्न मैंने पोलिस्टर फाइबर के आयात के बारे मे पूछा था उस का जो जवाब मत्री महोदय के द्वारा दिया गया उसी पर यह आज की बहस आधारित है । मेरे प्रश्न के उत्तर मे मत्री महोदय ने कहा था जिन लोगो को पोलियेस्टर फाइबर आयात करने की छूट दी गई थी उस के बारे मे जानकारी इकट्ठा की जा रही है । और सदन के सभा स्थल पर रखा जाएगा लेकिन ढाई महीने के बाद भी मत्री महोदय ने पोलिस्टर फाइबर के आयात के बारे मे सदन को विश्वास मे लेने का काम नही किया। इसलिए सब से पहले मैं चाहूगा कि हम लोगो की ओर से और इस सदन की ओर से इन्होने अपने कर्तव्य को पूरा करने मे जो लापरवाही की है, उस को ले कर आप इनको फटकारिये, डांटिये ।

सभापति महोदय, इस के बाद यह सन्त प्रकाश भगवान दास का मामला राज्य सभा और इस सदन मे चल पडा । सोचने की बात यह है कि 6 अप्रैल, 1974 को एक आवेदन पत्र के द्वारा मैंने राष्ट्रपति जी से कहा था कि विदेश व्यापार मत्रालय मे बहुत बडे पैमाने पर गडबडी हुई है, घोटाला हुआ है और इस की निष्पक्ष जाच होनी चाहिए और इसी पत्र मे—यह 6 अप्रैल का पत्र है—मैंने आरोप लगाया था कि सन्त प्रकाश भगवान दास नाम की फर्म को यह नाइलोन, फिलामेंट यार्न और थ्रेड और बाद मे पोलिस्टर फाइबर आयात करने की छूट दी गई, बावजूद इसके कि चीफ कन्ट्रोलर ने और रिजर्व बैंक ने इस का कस कर विरोध किया था। इस के बाद अध्यक्ष महोदय की मारफत पत्र-व्यवहार मेरा भी चला, अटल जी का चला और दूसरे सदस्यो का भी चला लेकिन इन पत्रो के उत्तर मे जो कुछ भी मत्री महोदय ने कहा है, उस मे भी ईमानदारी से सभी बातो पर प्रकाश डालने का इन्होने प्रयास नही किया है और बातो को छिपाया है । इन्होने हम लोगो के प्रश्नो के उत्तर मे यह कहा है कि सन्त प्रकाश भगवान दास फर्म ने दो बार माग की थी कि उन के द्वारा जो निर्यात किया गया है, उस के बदले मे उन को आयात करने की छूट मिलनी चाहिए । दो दफा इन की अर्जियो को अस्वीकार किया गया था और उस के बाद 12 जनवरी, 1 71 को इन के प्रतिवेदन पर पुनर्विचार हुआ और मत्री के स्तर पर, विदेश व्यापार मत्री के स्तर पर इस के ऊपर यह निर्णय किया गया कि सन्त प्रकाश भगवान दास को नाइलोन और फिलमेंट यार्न और थ्रेड आयात करने की छूट दी जाएगी, लेकिन मैंने जो पूछा था कि क्या रिजर्व बैंक ने और चीफ कन्ट्रोलर ने विरोध किया था और उस के विरोध के बावजूद यह निर्णय लिया गया था, उस का आपने जवाब नही दिया । वह मैं आप को पढ कर सुनाता हू । मेरा प्रश्न यह था :

"At what level and on what date the decision to issue a letter of authority to the said firm for importing nylon yarn and thread/polyester fibre was taken, and whether this was not in opposition to the views expressed by the Reserve Bank and the Chief Controller as also in violation of the policy then in force?"

यह उन्होने जवाब दिया

"The decision to issue CCP and letter of authority for nylon yarn and thread was taken on 12th January 1971 at the level of the then Minister of Foreign Trade The decision to include polyester fibre was taken on 3rd March, 1971 again at the level of the then Minister of Foreign trade"

मैंने यह कहा था कि क्या उस समय की जो निर्धारित नीति थी, उस के यह बरखिलाफ था ? क्या रिजर्व बैंक और चीफ कन्ट्रोलर की राय के यह खिलाफ था । इस का कोई आप ने जवाब दिया है और आज की बहस के बारे मे यदि यही रूख आप अपनाएगे, तो इस बहस से कोई नतीजा निकलने वाला नही है । इसलिए यह एक सवाल उठता है कि राष्ट्रपति जी को पत्र लिखने के बाद भी महीनो तक इस के बारे मे कोई कार्यवाही नही हुई । विदेश व्यापार मत्री के बारे मे तीन प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को हम ने दिये थे पर उन पर कोई कार्यवाही नही हुई । तो एक दफा मै गिरी साहब से मिलने भी गया और मैने उन से कहा कि चार-चार प्रतिवेदन हम ने विदेश व्यापार मत्री के खिलाफ दिये है पर आप ने उन पर कोई कार्यवाही नही की । इस पर उन्होने कहा कि आप के जो प्रतिवेदन आते हैं वह मै प्रधान मत्री जी को भेज देता हू । इस पर मैंने गिरी जी से कहा कि इस का मतलब यह हुआ कि आप एक पोस्टमैन हैं और सो भी इतने खर्चीले पोस्टमैन ।

[श्री मधु लिमये]

तो सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि 6 अप्रैल को इस की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रपति जी के मारफत इस के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

दूसरा मेरा सवाल यह है कि यह जो नाइलोन यार्न और बाद में जिस का कन्वर्जन किया गया पोलिस्टर फाइबर में, इस का मूल्य क्या था। इस की जानकारी भी मैं चाहता हूं।

साथ ही साथ मैं यह चाहता हूं कि इस को जो बदल दिया गया, इम्पोर्टेड नाइलोन यार्न और थ्रेड को जो पोलिस्टर फाइबर में बदल दिया गया, क्या यह कानून के अनुसार था ? क्या इस में कानून की अवहेलना नही हुई और क्या इसलिए यह परिवर्तन नही हुआ क्योंकि पालिस्टर फाइबर में काला बाजार में ज्यादा मनाफा मिलता था ? इसलिए मंत्री महोदय से मैं इस का भी जवाब चाहता हू कि क्या कानून के द्वारा, रेड बुक के अनुसार इस कन्वर्जन की छूट दी गई थी।

चौथी बात इन्होने कही है इन्फोर्समेंट की। मेरे प्रश्न के उत्तर में ये कहते हैं मेरा प्रश्न था :

What were the findings of the CBI and on which date were they submitted to the Government?

इस के जवाब में ये कहते है :

Regarding the alleged over-invoicing the Enforcement Directorate took action and imposed a penalty of Rs. 15 lakhs on the party.

तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह 15 लाख रुपया वसूल किया गया है और अगर वसूल किया गया है, तो कब किया गया है ?

साथ ही साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर यह जुर्माना वसूल नहीं किया गया है, तो क्या इसका यह कारण है कि यह जो आप ने पोलिस्टर फाइबर के लिए छूट दी है, वह इस कारण दी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए इस फर्म के पास से 10 लाख रुपया लिया गया था क्योंकि जून, 1970 में मन्त्रि मंडल में परिवर्तन हुए और स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र को जो विदेश व्यापार मंत्री बनाया गया था तो उन को इसीलिए मंत्री नही बनाया गया था कि उन के जिम्मे यह काम दिया गया था कि निर्यात की बात को न देख कर वे कांग्रेस पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करें (व्यवधान) कांग्रेस कोष विकास के लिए वे काम करें। क्या उन को इस के लिए ही नही नियुक्त किया गया था ? अभी जिस दिन हम लोग 18 तारीख को चर्चा कर रहे थे और मेरा काम रोको प्रस्ताव था तो मैं ने यह कहा था कि 23 दिसम्बर को स्वर्गीय ललित बाबू और इंदिरा जी की मुलाकात हुई थी और उस में ललित बाबू को कहा गया था कि अब आप हटिये, लेकिन उस के बाद ललित बाबू के जो नजदीक के लोग हैं, उन से मै ने जानने की कोशिश की और उन्होंने मुझ से कहा कि आपने जो कहा था वह 101 प्रतिशत सही था और प्रधान मंत्री जी ने बिल्कुल असत्य बोला था। खैर इस की चर्चा तो मैं अभी नही करना चाहता हू लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हू कि जब ललित बाबू विदेश व्यापार मंत्री थे, तो उनके कार्यालय में जितने निर्णय किये गये, उन के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह था कि उन का काम यह था कि वे कांग्रेस के लिए चन्दा इकट्ठा करे।

जब कांग्रेस पार्टी के लिए यह सब काम वह करते थे तो बदनाम तो हो ही गए लेकिन उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेने के बजाय ललित बाबू ने ही उठाई। अब इस देश की जनता

धीरे धीरे इन बातों को पकड रही है । इन बा ों को आ ने छिपाया क्यों ? अगर आपके उद्देश्य नेक थे तो क्या मेरी इस चुनौती को आप स्वीकार करने के लिए तैयार है कि पोलिस्टर फाइबर के ही नही 1970 से ले कर आज तक ये आयात लाइसेंस के और लैटर आफ आथ रिटी के जितने भी मामले हुए है क्या उन तमाम को आप इस सदन की कमेटी के सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। आप अन-फाउंडिड बात की चर्चा कर रहे हैं। आप अब मेरी ओर देखने ही नही। जितने घोटाले हो गए, आप पाक हैं, आपके दामन पर कोई दाग नही तो आपका डर क्यो लगता है, आप पालियामैंटरी जाच के लिए तैयार हो जाए । अगर आप तैयार हो जाते हैं तो इस में सदन का जो समय बरबाद होता है वह नही होगा ।

ये लोग छिपाने की कला मे बहुत माहिर हो गए है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में ये कबूल करते हैं कि the CBI found them guilty of the allegation of cheating लेकिन हम लोगो को जो पत्न लिखते है उस में इसका उल्लेख तक नही करते है । इसलिए मे इस प्रश्न का आप आप जवाब दे कि यह चीटिंग का जो आरोप हुआ, क्या इसके बारे मे कोई क्रिमिनल केस इस फर्म के खिलाफ चलाया गया है ? साथ ही साथ यह सोचने लायक बात है कि इस फर्म के बारे मे एबेंइंस का आदेश जारी किया गया है और सरकार ने परिपत्न जो जारी किया था, काशनरी स र्युलर जिस को वह कहते है, तो पहले मत्नी महोदय के स्तर पर निर्णय लिया गया कि इनको लेटर आफ आथोरिटी दिया जाएगा नायलोन यार्न के लिए लेकिन जो लैटर आफ आथोरिटी था उसको परिवर्तित किया गया पोलिस्टर फाइबर के लिए और उसके बाद यह एबेएस आर्डर और काशनरी सक्यु लर वापिस लिया गया, क्या यह सही नही है और यदि हां, तो क्या इससे भी यह बिल्कुल साफ नही हो जाता कि केवल सन्त प्रकाश भगवान दास फर्म को ही नही, पोलिस्टर फाइबर आयात करने वाले जितने लोग हैं उन लोगों के बारे मे इस तरह का अवैध और गैर कानूनी काम हुआ है । इस वास्ते मैं चहता हू कि मेरे प्रश्न के उत्तर में जो जानकारी देने का आपने वचन दिया था आप अपने जवाब में सब ऐसी फर्मों के बारे और व्यक्तियो के बारे में जो जानकारी हमने मागी थी वह दे ।

साथ-साथ आप तो जानते है कि पोलिस्टर फाइबर के ऊपर प्रीमियम है और इस प्रीमियम के बारे मे समय समय पर सरकार के पास जानकारी आती रहती है । अब क्या इन फर्मों का इनकम टेक्स एसेस करते समय बाजार में पोलिस्टर फाइबर का जो असली दाम था उसको आका गया था और उसके आधार पर इनकम टैक्स एसेस कियागया था ? अगर नही किया गया तो इन फर्मों को छूट देने का कारण क्या है और इन लोगो से काग्रेस पार्टी के लिए कुल कितना चन्दा आपने एकत्न किया है, इसका विवरण भी आप हमें दे ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) . मत्नी महोदय जवाब दे ले, उसके बाद हम प्रश्न पूछेंगे और वह भी तब अगर हमें उन के उत्तर से सन्तोष नही होगा । हो सकता है कि उनके उत्तर से ही हमे सतोष हो जाए ।

THE MINISTER OF COMMERCE (PROF D P CHHATTOPADHYAYA): It is upto you Mr Chmairman.

MR. CHAIRMAN: I do not know which is the procedure

श्री मधु लिमये नियम तो यही है कि मत्नी महोदय प्रश्नो के बाद उत्तर दे लेकिन नियमो को हमेशा सुविधा के अनुसार एडजस्ट किया जाता है । सुविधा इसी में है कि मेरे प्रश्नो का वह जवाब दे दे और जिन

[श्री मधु लिमये]

बातो का खुलासा वह न करे उनको ,तथा अपने प्रश्नो को मेरे मित्र पूछ ले।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमड हार्बर) प्रधान मत्री का गुरु इस मे फसा हुआ है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी साहब योगाश्रम वाले ..

MR CHAIRMAN Mr Bosu during the half-an hour discussion, only those who are listed can speak

The rule says

SHRI JYOTIRMOY BOSU Sir, I rise on a point of order

I have received a letter from the Commerce Minister written to me which says

> 'Kindly refer to your letter of December 22 1974 I have made certain informations available to the hon Speaker, Lok Sabha, regarding the import of polyester fibre by the firm Messrs Sant Prakash Bhagwan Das in pursuance of my submission made on the floor of the House I have no objection if these informations are communicated to you"

In continuation of this I wrote a letter to the hon Prime Minister, I quote

> "I shall be grateful if you will be good enough to give more details of this case of the said Swamy's detailed involvement in the matter of issuance of this licence

So far I have not got the fortune of getting the reply I am sitting here upto this fag end of the day to know as to how much corruption has gone into this Government

MR CHAIRMAN This is not relevant at this moment when we are giving half an hour discussion

श्री मधु लिमये इन्होंने कहा था कि मैं सारी जानकारी दे दूगा यह उन्होने 6 दिसम्बर के मेरे प्रश्न के उत्तर मे कहा इनको वह पहले दे ताकि इनके जवाब के ऊपर हमे सोचने का मौका मिले। इनको मैं खास तौर पर चेतावनी देना चाहता हू कि इनके ऊपर अब जिम्मेदारी आई है फड कलैक्शन की। जो फड कलैक्शन के मामले में गहराई में जाता है उसकी जान हमेशा खतरे में होती है, यह ललित बाबू की घटना से व्यवस्था ने, एस्टेबलिशमेंट ने साबित किया है। आप मेरे मित्र हैं। इसलिए मैं आप से प्रार्थना करता हू कि बच कर रहे। डिक्टेटर को जिन के रहस्य मालूम होते है या डिक्टेटर के जिनको रहस्य मालूम होते है वे सब खतरे मे रहते है।

MR CHAIRMAN The practice is immediately after the discussion is raised, the hon Members whose names come in the ballot put their questions to the Minister who replies to all these points at the end of the discussion

SHRI JYOTIRMOY BOSU. It is very much in the air that the hon. Minister has been chosen to collect Rs 2 crore from the jute magnates and today the Jute Corporation has become defunct

श्री मधु लिमये . दो करोड का मै नही जानता हू। मैं तो चाहता हू कि जो सवाल मैंने उठाए हैं उनका मुझे ये जवाब दे दें।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA. Sir, my question is very simple and I would not like the Minister to evade it in any way My simple question is Whether this particular firm was prosecuted by the Enforcement Department and a fine of Rs 15 lakh was imposed on them and whether that fine remains unrealised or at least remained unrealised till the issue of this clearance certificate?

Secondly, would the Minister be in a position to tell us as how many times representations had been made by the party to the Government and on what grounds they were rejected? Please, give the details of it and also the details of the grounds of rejection

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : सभापति महोदय, देश में अभी तक पांडीचेरी लाइसेंस कांड की चर्चा हो रही थी, लेकिन इस समय जिस काड पर विवाद हो रहा है, वह पांडिचेरी लाइसेंस काड को भी मात करने वाला है। एक फर्म, सन्तप्रकाश भगवानदास, को डीरजिस्टर किया गया था, लेकिन उन्होने 1967 में लाइसेस मागा। श्री दिनेश सिंह विदेश व्यापार मंत्री थे। उन्होने आवेदन स्वीकृत कर दिया। 1968 में श्री बलिराम भगत विदेश व्यापार मंत्री थे। उन्होने भी आवेदन ठुकरा दिया। लेकिन 1971 में उस फर्म को लाइसेस दे दिया गया।

क्या यह सच है कि नाइलोन यार्न थेड और पालिस्टर फाइबर के आयात का काम स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन का था, लेकिन इस मामले मे स्टेट ट्रेडिग कार्पोरेशन को ताक पर रख दिया गया और इस फर्म को यह माल मगाने का अनुमति-पत्र दे दिया गया? यह उपवाद करने की क्या आवश्यकता थी?

इस फर्म ने दावा किया था कि उसकी 18 लाख की मुद्रा अफगानिस्तान मे जमा है। उसने अफगानिस्तान को माल भेजा था। उसके बदले में उसने पूजी कमाई थी, जो वहा जमा है, और उस जमा पूजी को वापिस लाने के लिए उसने लाइसेंस मागा था। क्या यह सच है कि कस्टम क्लीयरेंस परमिट देने से पहले रिजर्व बैंक से इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा नही की गई कि अफगानिस्तान मे उस फर्म की कितनी मुद्रा जमा है और लाइसेस दे दिया गया?

क्या यह सच है कि जब इस फर्म को लाइसेस दिया गया, तो टैक्सटाइल कमिश्नर ने यह शर्त लगाई थी कि जो माल मंगाया जायेगा, वह एक्चुअल यूजर्ज को दिया जायेगा, लेकिन फर्म ने एक्चुअल यूजर्ज को माल नहीं दिया और उसको काले बाजार में बेचा? जब फर्म से यह पूछा गया कि उसने यह क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि उस समय के मंत्री महोदय से बात हो चुकी थी और मंत्री महोदय ने कहा था कि तुम जिसको चाहे माल बेच सकते हो। फर्म की तरफ से इस तरह का लिखा हुआ फाइल में मौजूद है। क्या सरकार ने पता लगाने का प्रयत्न किया है कि उस समय के मंत्री महोदय ने यह छूट क्यो दी थी कि वह फर्म जिस को चाहे माल बेच सकती है?

मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में जितने भी इम्पोर्ट लाइसेंसिज दिये गये हैं, उन सब की एक कमीशन या पार्लियामेंट की कमेटी जाच करे। मेरे पास एक मामला है। मैंने इस बारे में प्रधान मंत्री को लिखा था। कानपुर में स्वदेशी मेटल वर्क्स को 40 लाख रुपये का स्टेनलैस स्टील इम्पोर्ट करने का लाइसेस दिया गया। यह लाइसेंस 26 जनवरी, 1971 को जारी किया गया। 26 जनवरी, को केन्द्रीय सचिवालय बन्द रहता है, लेकिन उस दिन यह लाइसेस जारी किया गया। गणराज्य दिवस का समारोह था, सारे देश मे छुटटी थी। क्या मंत्री महोदय घर से लाइसेस जारी करते थे? स्टैनलैस स्टील को चोर बाजार में बेच दिया गया और 300, 400 परसेंट का मुनाफ़ा कमाया गया। वह मुनाफा कहां गया?

स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र के समर्थक अखबार लिख रहे हैं कि वह कांग्रेस पार्टी के सब से बड़े फ़ंड-रेज़र थे। ब्लिट्ज़ ने लिखा है कि पंडित उमाशंकर दीक्षित जैसे आदमी स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के दरवाजे पर बैठे रहते थे, एक बार नही, अनेक बार नेशनल हेरल्ड के कर्मचारियों के लिए तनख्वाह मांग कर लाते थे। क्या लाइसेंस दे कर यह रुपया कमाया गया?

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

मृत व्यक्ति के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सारी प्रणाली दूषित हो गई है। व्यक्ति से हमारा झगडा नहीं है व्यवस्था से झगड़ा है।

मंत्री महोदय बतायें कि इस बारे में जो जांच चल रहा थी, उस का क्या परिणाम निकला है। वह यह भी बतायें कि क्या सरकार इस मांग को मानने जा रही है कि पिछले तीन सालों में जितने भी इमपोर्ट लाइसेंसिज दिये गये हैं, उन सब की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाये।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: He can enumerate what were the reasons for the firm being blacklisted.

MR. CHAIRMAN: You can ask at the appropriate time.

SHRI S. A. MURUGANANTHAM (Tirunelveli): Is it a fact that the import licence was issued to a Bombay blacklisted firm, Messrs. Sant Prakash Bhagwandass to import polyster fibre from Singapore and subsequently the firm sold the licence? Has the Government made any investigation regarding this malpractice? Will Government refer to its answer to parts (c) to (e) of starred question No. 352 and say whether the information has since been collected? If not, how long do Government propose to take to collect the information sought?. What was the total quantity of polyster fibre imported through STC during 1973-74 and how many letters of authority were issued during this period?

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): This is a very grave question again coming up for our attention. I feel this is only the beginning of a deeper analysis required in this House.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Tip of the iceberg.

SHRI SEZHIYAN: We are not concerned with who did it; we are concerned with what was done and how it was done, because the Government is a continuing one and irrespective of the person who occupied a particular position at a particular stage, it is the Government that should answer. I hope the Minister will give, to the best of his ability, in spite of his evasive capacity, answers to the questions raised here.

A question was raised by Shri Madhu Limaye and others about the fine imposed by the Enforcement Directorate. Has this been collected? If not, what are the reasons that it was allowed to remain uncollected? The original licence was granted on 12 January 1971 for nylon yarn and it was converted on 3 March 1971 to ployster fibre.....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Not converted, added.

SHRI SEZHIYAN: Added. Has there been a change in the policy and rules in the Red Book between these two dates, 12 January 1971 and 3 March 1971? I would also like to know whether there are any other cases where such conversions have been allowed by Government between these two dates or beyond these dates also.

I want to raise a basic question because trafficking in import licences has been a phenomenon well known to Government and connived at by Government. This is only the symptom of a disease, only the tip of the iceberg. These one or two cases we have come across, the Pondicherry licence scandal and the polyster fibre case, these are only symptoms of a deeper disease.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Monument of corruption.

SHRI SEZHIYAN: Therefore, I would like to know whether he is prepared to face a parliamentary committee to go into the entire aspect and the practice of the grant of licences

and the impact it has got on smuggling, black money and other aspects. Licensing seem to be the fountain of all the corrupted money in this country. Therefore, is he prepared for the appointment of a parliamentary committee to go into the entire aspects of this question?

MR. CHAIRMAN: Prof. Chattopadhyaya.

SHRI PILOO MODY (Godhra): I endorsed all these questions.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I would ask a question with your permission.

MR. CHAIRMAN: How can you?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: What is the involvement of Shri Dhirendra Brahmachari who runs a Yogashram here. who has been very close to the Prime Minister for years, a person who had received lakhs of rupees from different quarters as grants, the man who was sent to the International Exhibition in Tokyo with his disciples, male and female? We would like to know how much involvement of Dhirendra Brahmachariji is there in this *kala* business....

MR. CHAIRMAN: You know very well that under rule 55(2), nobody else can intervene. It will be unfair to those who are eligible to participate in this discussion. It has been balloted and only four members have secured their place in the ballot. If I allow you to speak, it will be unfair to the other members.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am only trying to seek a clarification.

18.00 hrs.

PROF. D. P CHATTOPADHYAYA: I am on my legs I must first like to say that prefixing and suffixing questions with wild and absolutely baseless allegations is extremely unfortunate.... (*Interruptions*). I stand by what I have said. The question of corruption is quite different from the question of taking decisions. The question of fund raising and other things attributed to my predecessor and the Ministry is extremely unfortunate. It has become almost a habit to say all these things whenever they raise such questions. If that is the way they want to do it, if that is the level to which they want to reduce this, it will not serve the purpose that I believe they have in their mind. Nor is the country and this House interested in bringing the discussion down to that level. Every year the Ministry issues two lakhs of licences. They take out two or three or four cases

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I have many more.

SHRI PILOO MODY: If there are two lakhs of licences that the Ministry issues, you can be sure that there must be at least 2½ lakhs cases of corruption ..(*Interruptions*).

PROF D P. CHATTOPADHYAYA: They are citing two or three stray cases and dramatising those things; it is extremely unfortunate. As they have prefaced their questions with so many wild allegations, I must set the record straight.

Secondly, we are as much interested as they are in weeding out corruption. We have not suppressed anything. Take the questions they have asked. All the correspondence is with the Lok Sabha Secretariat, with the hon. Members. You look at facts and figures. Almost all questions they have asked, we have answered Certainly they do not expect me to answer questions about which factually I am not yet quite sure, because they are very wise parliamentarians and they ask me questions about facts which I am unsure of and then they will bring motion of breach of privilege. Mr. Madhu Limaye is specialist in bringing privilege issues... (*Interruptions*).

The second point I should like to make is this. For the questions they have asked, whatever facts and figures are available with me, I am prepared to satisfy them about the correctness.

[Prof. D. P. Chattopadhyaya]

With respect to some other questions they have asked. I am looking into them and whenever I get answers to those questions, I shall make them available.

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad). On a point of order. I am on a serious point of order. I am not saying anything about what he said in the beginning. He has a right to reply forcefully to the charges made. But when he came to the specific questions and started answering them, he said that he was unsure of several factors. When the Government are unsure of several facts about which a discussion has to take place, why did they agree to have a discussion? They can say: we are still unsure of facts. Let us be sure of facts and then we will have a discussion. Otherwise the whole purpose of discussion is lost; the opportunity to focus attention of the country on important matters is lost. Are you going to have a second discussion on this? If you are not going to have a second discussion. I suggest that you give guidance, if the Minister is not sure of facts, let him collect them. We are sympathetic. Let us postpone this to another day so that he can come with more surety and certainly about facts.

MR. CHAIRMAN: He said earlier that all the relevant files are before the Lok Sabha Secretariat and hon. Members could see it. What he was saying, if I understood him correctly, was that he could not remember all those files.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: No files are available.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: I did not say that. I said, they have raised certain questions which I cannot answer without checking up the facts. For example, what was the Reserve Bank's attitude? What about income-tax clearance? Such questions were asked. Unless I check up these facts with the Reserve Bank, the customs and the income-tax authorities, I can't answer them.

श्र: मधु लिमये : कितने दिन लगते हैं ? यह क्या है? सीरियस प्वाइंट श्राफ श्रार्डर यह उठता है । उन्हें इस का जवाब देना चाहिए । वे कहें कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: He knows everything but he is deliberately withholding information from the House. It is a very serious matter, a contempt of the House. He has had sufficient notice.

MR. CHAIRMAN: About Mr. Mavalankar's point of order, Rule 55(5) says:

> "The member who has given notice may make a short statement and the Minister concerned shall reply shortly."

In a brief reply you cannot expect so many details concerning various matters.

SHRI P. G. MAVALANKAR: I am not concerned with whether his reply is short or long. But he must be sure of his facts.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: On 26th December, the minister wrote a letter saying,

> "The question of receipt of reply from the Reserve Bank of India for regarding the funds of the party abroad is being ascertained."

By now he must have ascertained. Let him inform the House.

MR. CHAIRMAN: The minister may give a reply on whichever facts he is aware of.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: They want to shield people very close to the Prime Minister. That is the simple reason.

MR. CHAIRMAN: Don't bring in extraneous matters.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Sir, it has been asked whether these licences were issued in the face of opposition by the Chief Controller of Imports and Exports and the Reserve Bank of India. I will say that there was no opposition to this proposal either from the office of the CCIE or the office of the Reseve Bank.

Then he asked whether polyster fibre import was according to the rules. According to the Indo-Afghan trade prevalent at that time, this was not a permissible item.

SHRI MADHU LIMAYE: So, you agree it was illegal?

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: You know English very well. You can interpret it.

SHRI MADHU LIMAYA: Let everybody know it.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: It is not provided in the agreement. I do not believe in equivocation. I am stating it very clearly.

The third point is about the penalty imposed. A penalty of Rs. 15 lakhs was imposed, against which they have preferred an appeal. We do not know whether the appeal has been disposed of. I am checking it up. But I know the penalty was imposed and they have preferred an appeal against the penalty.

SHRI MADHU LIMAYE: Before whom?

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Before the appellete authority.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On what date?

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: I do not know the date. I know the penalty was imposed and an appeal has been filed by the party.

There was a question whether it was rejected earlier. Yes, it was rejected before.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: How many times?

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: My record suggests twice. Some of these things are within the knowledge of the hon. Members because I have mentioned them in my letter to them.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: We want to know in the House the grounds for rejection.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: One ground was that we did not think they have money accumulated abroad. There was a doubt at that time whether there was money accumulated abroad. That was the main question. But a matter which is once rejected at the Minister's level can always be reopened. There is nothing surprising about it. A Minister can reopen questions, if he is satisfied that it is necessary. Sometimes it is necessary, if some injustice has been done.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: What was the price for reconsideration?

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Why are you asking these extraneous questions?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Sir, may I seek your indulgence? When the representations were made, were the grounds of rejection identical? Please tell us the grounds of rejection at the time of the first representation and also at the time of the second representation. I want you to clarify that.

MR. CHAIRMAN: Under the rules only one question can be asked.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I am not asking a new question.

MR. CHAIRMAN That is why I am indulgent. But you nust bear in mind that under the rules only one question can be put and there will be a short reply. This cannot be carried on as a discussion and other members cannot ask questions.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA I have already said that there was a doubt about the fact whether this firm had money abroad to counterbalance the imports. That was the point. Later on, it was reviewed. There is nothing wrong in reviewing the matter merely because it was rejected before.

SHRI JYOTIRMOY BOSU What about the other grounds for rejection?

PROF. D P CHATTOPADHYAYA I am coming to them One of the grounds of rejection was that it was not provided for by the Indo-Afghan trade.

SHRI SEZHIYAN What were the other grounds?

SHRI SHAYMNANDAN MISHRA Please tell us what were the grounds on both the occasions?

PROF. D P. CHATTOPADHYAYA Why are you repeating the same point? I have said that it is not provided by the rules of the Indo-Afghan trade.

Therefore, it was not agreed That is what I have said.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On what ground did you reconsider to grant it?

SHRI SHAYMNANDAN MISHRA They had doubts about their funds abroad and it was not included in the Indo-Afghan trade. These were the two grounds. Do we understand that?

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA. We have no intention to suppress any fact These facts are with the Reserve Bank and the income-tax authorities. We are checking up these facts. If something wrong is brought to light and some persons have indulged in going something wrong, whether he is in the Ministry or outside the Ministry, he will be suitably and firmly dealt with. I can categorically assure you of that. We are interested in these facts, but we do not believe that a parliamentary inquiry is suitable or necessary for these things. We can administratively deal with it and we will deal with it.

श्री मधु लिमये क्या चीटिंग के लिये क्रिमनल केस किया ? सभापति महोदय, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नही आया, मेरे दोनों प्रश्नो का उत्तर दिलवाइये ।

PROF D P CHATTOPADHYAYA I have said it already in my communication There was a CBI case against the party, but it was in quite a different connection, that was in respect of export and import of hides and skins There was a conviction against the party They have preferred an appeal against that That is before the court

SHRI JYOTIRMOY BOSU When was that?

PROF D. P. CHATTOPADHYAYA· Much earlier.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You are keeping it on fire and are allowing him to suck the blood of the country.

PROF. D P. CHATTOPADHYAYA: We are dealing with the facts. If according to the law, he has gone to the court, it is for the party to go and for the court to decide.... (In-

terruptions). I have already written to him about this: I am not saying it only now.... (*Interruptions*).

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I had asked a specific question .. (*Interruptions.*) I wanted to know whether it is not a fact that, when the firm was asked to explain why the imported material was not given to actual users, it was replied on behalf of the firm that Messrs Sant Prakash Bhagwan Das had a private talk with the Minister concerned and the Minister had given them an assurance that the firm was free to sell the material to any firm or to any party they liked. Is it not a fact that this information is recorded in the file concerning this firm?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Is it also a fact.. ..

MR. CHAIRMAN: I am not allowing you.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: I have already said about the CBI case against this firm. I am just informed that the court discharged these people. It is not about this one but the other CBI case about hides and skins. Government has preferred an appeal against the party to the court and it is pending.

What discussion, if at all, took place between the Minister and other people. I do not know. But I can tell you that we served a show-cause notice on these people asking them to tell who are the actual users to whom they were supposed to sell these imported goods. I have also checked up the facts with the Textile Commissioner's office. I find that some of the actual users have not got the materials. That is the party did not sell the imported goods to them. It is an irregularity that they have committed. The original condition was that they could sell it and they should not earn more than 20 per cent profit. The Ministry took the caution so that they did not make huge profit or get undue premium on the sale. That condition was attached. But an inquiry reveals that they have flouted the condition attached to the original Import Order.

As I have said, I only repeal, if they are found to have violated the rules and regulations and conditions attached, they will be firmly and suitably dealt with.

18.22 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clockon Tuesday, February 25, 1975/*Phalguna* 6, 1896 (*Saka*).

MGIPND—L—3507 LS—16-4-75—978.